www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 160 | जौनपुर शनिवार, 24 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

धार भोजशाला में नमाज और पूजा एक साथ

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर धार स्थित भोजशाला में आज बसंत पंचमी का पर्व बेहद खास और संवेदनशील माहौल में मनाया जा रहा है। सूर्योदय के साथ ही हिंदू पक्ष ने मां वाग्देवी (सरस्वती) की विशेष पूजा–अर्चना शुरू कर दी है। ये पूजा सूर्यास्त तक जारी रहेगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश के तहत दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम समाज परिसर में जुमे की नमाज भी अदा करेगा। पूजा और नमाज के समय को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ (ब्श्रप् सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली) ने 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है।कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक (1 से 3 बजे के अंतराल को छोड़कर) पूर्ण पूजा की छूट दी है, जबकि मुस्लिम पक्ष को 1 से 3 बजे के बीच नमाज की अनुमति मिली है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था के लिए विशेष पास और अलग–अलग स्थानों की व्यवस्था की जाए।किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। धार शहर को छावनी में बदल दिया गया है, जहां सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस के 8 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में एआई तकनीक वाले कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है।

बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को विधि –विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वसंत पंचमी पर आज बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। इससे पहले गुरुवार को डिम्मर से डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्य गाडू घड़ा के साथ ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को पुजारी गाडू घड़ा लेकर नरेंद्रनगर राज दरबार पहुंचे। यहां परंपरागत तरीके से भगवान बदरीविशाल धाम कपाटोद्घाटन की तिथि घोषित की गई।भगवान बदरीविशाल के कपाट 23 अप्रैल को ब्रह्म काल मुहूर्त पर 6रू15 पर खोले जाएंगे। गाडू घड़ा यात्रा सात अप्रैल को आरंभ होगी। श्रीलक्ष्मी–नारायण मंदिर डिम्मर में बृहस्पतिवार सुबह डिम्मर गांव के पुजारी टीका प्रसाद डिमरी और आचार्यों ने भगवान और गाडू घड़ा की विष्णु सहस्त्रनाम और नामावलियों से महाभिषेक पूजा कर बाल भोग अर्पित किया। इसके बाद बदरीनाथ धाम के डिमरी पुजारियों ने गाडू घड़ा लेकर मंदिर की परिक्रमा की। फिर भगवान श्रीबदरी विशाल के जयकारों के साथ यात्रा रात्रि प्रवास के लिए ऋषिकेश रवाना हुई।वसंत पंचमी को सुबह गाडू घड़ा लेकर डिमरी पुजारी ऋषिकेश से नरेंद्र नगर राजदरबार पहुंचें।

पूरे देश के लिए आदर्श शहर बनेगा तिरुवनंतपुरम : प्रधानमंत्री मोदी

केरल, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुर नगर निगम में भाजपा की ऐतिहासिक की जीत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की ओर से दशकों से की जा रही उपेक्षा के अंत और विकास व सुशासन के नए युग की शुरुआत का संकते है। प्रधानमंत्री ने दोनों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, एलडीएफ और यूडीएफ ने अलग–अलग तरीकों से

केरल को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और तुष्टिकरण की राजनीति के दुष्चक्र में धकेल दिया है। भले ही उनके झंडे और प्रतीक अलग हों, लेकिन उनकी राजनीति और एजेंडा लगभग एक जैसे हैं– बेलगाम भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और विभाजनकारी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। दोनों दल जानते हैं कि हर पांच साल में उन्हें शासन का मौका मिलता है। लेकिन बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। उन्होंने आगे कहा, दशकों तक एलडीएफ और यूडीएफ ने तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा की और शहर को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। वाम दल और कांग्रेस जनता की जरूरतों को पूरा करने में लगातार नाकाम रहे हैं। लेकिन हमारी टीम भाजपा ने विकसित तिरुवनंतपुरम की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इस शहर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं– भरोसा रखें, जिसका इतंजार लंबे समय से था, अब वह बदलाव आने वाला है। तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत की तुलना अहमदाबाद से क्यों की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया।

द्रौपदी मुर्मू दो फरवरी से ओडिशा के छह दिवसीय दौरे पर रहेंगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो फरवरी से ओडिशा के छह दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह अपने गृह जिले मयूरभंज में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगी और अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ बालासोर स्थित एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुर्मू दो फरवरी की शाम को भुवनेश्वर पहुंचेंगी और रात्रिविश्राम लोक भवन में करेंगी। बयान में कहा गया है कि तीन फरवरी को वह सुबह जाजपुर में मां बिरजा मंदिर में पूजा–अर्चना करेंगी और फिर फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए बालासोर जाएंगी। शाम को वह पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जाएंगी। राष्ट्रपति चार फरवरी को अपने गृह जिले मयूरभंज का दौरा करेंगी जहां वह रायरंगपुर के महुलदिहा में एक 'हॉलिडे होम' (छुट्टियां बिताने वाले स्थान) का उद्घाटन करेंगी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित एक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा करेंगी। वह भंजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करने और बैदपुर में एक खेल परिसर का उद्घाटन करने के साथ–साथ रायरंगपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी तथा कुछ का उद्घाटन करेंगी। बयान में कहा गया है कि मुर्मू पांच फरवरी को रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी और सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान का भी दौरा करेंगी।

गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में करेंगे पतंजलि इमरजेंसी अस्पताल का लोकार्पण

हरिद्वार, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को हरिद्वार जाएंगे और कई महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री बुधवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे। इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवा, आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो परंपरा में निहित समग्र विकास पर सरकार के जोर को दर्शाता है।गुरुवार को उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10 बजे पतंजलि योगपीठ के महर्षि दयानंद ग्राम में होगा, जहां वे पतंजलि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल के उद्घाटन से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के काफी मजबूत होने और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर इलाज मिलने की उम्मीद है। सुबह 10रू45 बजे अमित शाह गायत्री तीर्थ शांतिकुंज पहुंचेंगे, जहां वे अखंड ज्योति पर प्रार्थना करेंगे और गायत्री परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। यह दौरा राष्ट्रीय जीवन में गायत्री परिवार के आध्यात्मिक और सामाजिक प्रभाव को उजागर करता है।केंद्रीय मंत्री हरिद्वार के बैरागी द्वीप में परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्शताब्दी वर्ष समारोह 2026श में भारत और विदेश से भक्तों और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। शाह सभा को संबोधित करेंगे और सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जागृति में गायत्री परिवार के स्थायी योगदान के लिए उसकी सराहना करेंगे।

भारत को अपने कार्यों से विश्व को गरिमा सिखानी चाहिए : मोहन भगवत

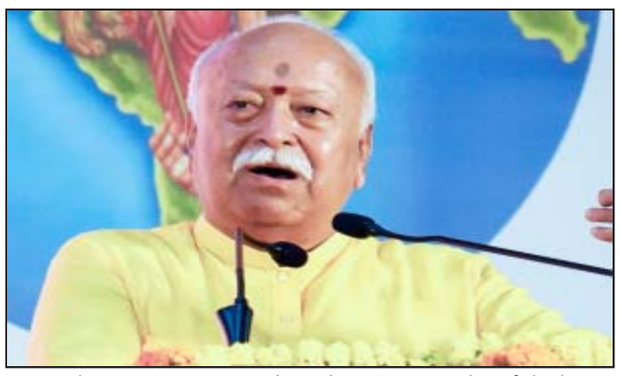

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भगवत ने कहा कि भारत को अपने कार्यों से विश्व को गरिमा सिखानी चाहिए, न कि केवल भाषणों या पुस्तकों से। संघ के सरसंघचालक ने कहा कि पुस्तकों और भाषणों से प्राप्त ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची सीख आचरण से मिलती है, जो समय के परिवर्तन के बावजूद शाश्वत सिद्धांत है। गुरुवार को दीदवाना–कुचामन जिले के छोटी खाटू कस्बे में मर्यादा महोत्सव में सभा को संबोधित करते हुए भगवत ने कहा कि विश्व को गरिमा सिखाना भारत का कर्तव्य है। उन्हें यह भाषणों या पुस्तकों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से सिखाएं। पुस्तकों में ज्ञान है और लोग भाषण सुनते हैं, लेकिन इससे प्रक्रिया पूरी नहीं होती। मोहन

भगवत ने कहा कि आचरण और व्यवहार शाश्वत है। यह बात एक हजार साल पहले कही गई थी और आने वाले समय में भी कही जाती रहेगी। लेकिन हजार साल पहले परिस्थितियाँ अलग थीं। आज परिस्थितियाँ भिन्न हैं। भगवत ने कहा कि जहाँ दुनिया इस बात से अनभिज्ञ है, वहीं भारत के पूर्वजों ने यह समझा था कि विभिन्नताओं के बावजूद सभी मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं, और इस एकता के साथ जीने से गरिमा आती है, जिसे उन्होंने श्धर्मश का सिद्धांत कहा। उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया को एक महत्वपूर्ण बात का पता नहीं चला। हमारे पूर्वजों को इसका ज्ञान था। वह क्या है? हम भले ही एक–दूसरे से भिन्न दिखें, लेकिन हमारी बुनियाद में हम एक हैं। इसीलिए भले ही हम भिन्न दिखें, लेकिन हम एक हैं – इसे याद रखें। एक होने का अर्थ है कि हर कोई हमारा है। यदि हर कोई हमारा है, तो गरिमा अपने आप जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है... इस संसार में जीवन निरंतर चलता रहता है। जो इसे गतिमान रखता है, उसे श्धर्मश कहते हैं। बाकी दुनिया इस श्धर्मश को नहीं जानती क्योंकि वे इसके पीछे के सत्य को नहीं जानतेय हमारे पूर्वज इसे जानते थे। इससे पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भगवत ने 18 जनवरी को कहा था कि धर्म समस्त अस्तित्व का प्रेरक बल है और संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है।

शशि थरूर कांग्रेस की अहम मीटिंग में शामिल नहीं होंगे

केरल, (एजेंसी)। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पार्टी के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने राज्य चुनाव की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, थरूर का यह कदम हाल ही में कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुए श्अपमानश के प्रति उनके कड़े विरोध को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार, यह फैसला तब लिया गया जब थरूर को कोच्चि में एक महापंचायत कार्यक्रम में ष्अपमानितष महसूस हुआ, जहां पार्टी सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। अहम चर्चा मीटिंग से थरूर की गैरमौजूदगी हाई–स्टेक वाले राज्य चुनावों से पहले पार्टी के

अंदरूनी मतभेद का संकेत देती है। कांग्रेस सूत्रों ने संकेत दिया है कि वह फिलहाल कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों से नाराज हैं, जिसके कारण उन्होंने मीटिंग में शामिल न होने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर ने अपने करीबी सहयोगियों को अपनी निराशा बताई है, और कहा है कि यह घटना पार्टी के अंदर उनके योगदान की अनदेखी के एक बड़े पैटर्न को दिखाती है। कोच्चि इवेंट में, बैठने और बोलने के शेड्यूल को लेकर दिक्कतें आईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, थरूर को बताया गया था कि उनके बाद सिर्फ राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन बाद में दूसरे नेताओं ने भी भाषण दिया। व्यवस्थाओं को लेकर यह कन्फ्यूजन सार्वजनिक अपमान के तौर पर देखा गया, खासकर कांग्रेस में थरूर की वरिष्ठता को देखते हुए। शुरुआती निर्देश के बावजूद, राहुल गांधी के आने के बाद कई अन्य पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, तय प्लान से यह बदलाव थरूर की नाराजगी का कारण बना, खासकर वक्ताओं के क्रम के संबंध में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए। इस घटना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आंतरिक अनुशासन और वरिष्ठ नेताओं के सम्मान के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। महापंचायत में अपने भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने थरूर का नाम नहीं लिया। पर्यवेक्षकों ने कहा कि थरूर की पार्टी और राज्य में प्रमुखता को देखते हुए यह बात ध्यान देने योग्य थी।

आंध्र प्रदेश की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए दावोस दौरा उपयोगी : चंद्रबाबू नायडू

अमरावती, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि दावोस की उनकी यात्रा आंध्र प्रदेश की ब्रांडिंग को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद रही है। गुरुवार को अपनी यात्रा खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्लेटफॉर्म ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदलते ट्रेंड्स और दुनिया भर के इंडस्ट्रियल दिग्गजों के नजरिए को समझने में मदद करता है।मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन दिनों में हुई अलग–अलग मीटिंग्स के जरिए, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और टूरिज्म जैसे अहम सेक्टरों में राज्य की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पेश किया गया।मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, उन्होंने कहा कि अब ग्लोबल कॉर्पोरेट दिग्गज भारत में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने यह राय जाहिर की कि युवा शक्ति, प्रभावी नेतृत्व और इन्वेस्टर–फ्रेंडली नीतियों के कारण, भारत में सभी सेक्टरों में कंपनियां स्थापित करने के अवसर काफी बढ़ गए हैं। विशाखापत्तनम में टीसीएस डेवलपमेंट सेंटर, अमरावती में प्रस्तावित क्वांटम वैली और कुरनूल में प्रस्तावित सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा हुई।चार दिवसीय दावोस यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ने 36 से ज्यादा मीटिंग्स में हिस्सा लिया। उन्होंने इजरायल, यूएई और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों के साथ तीन मीटिंग्स में भाग लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेन्यू पर, मुख्यमंत्री 16 ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडर्स से मिले। उन्होंने नौ से ज्यादा सेशन और मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश ब्रांड को विश्व स्तर पर और बढ़ावा देने के लिए राज्य में लागू की जा रही विभिन्न नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अहम भूमिका निभाई। अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ने यूरोप में रहने वाले तेलुगु लोगों के साथ करीब से बातचीत की और तेलुगु डायस्पोरा कार्यक्रमों के जरिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाया।

रामकथा में रेखा गुप्ता का संकल्प, वेतन समर्पित विश्व शांति मिशन को

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मोरारी बापू की नौ दिवसीय रामकथा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए अपने एक माह के वेतन की राशि समर्पित करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मोरारी बापू की रामकथा सेवा, करुणा और राष्ट्र के नैतिक संस्कारों का संदेश देती है। यह आयोजन समाज में सकारात्मक चेतना जागृत करता है।इसके पश्चात जैन आचार्य लोकेश मुनि के मार्गदर्शन और प्रेरणा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र द्वारा निरंतर किए जा रहे सेवा, सद्भाव और लोककल्याण के कार्य अत्यंत प्रेरणादायक हैं। आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक चेतना, अहिंसा और विश्व शांति के संकल्प को सशक्त करता है।इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री द्वारा विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए एक माह का वेतन समर्पित करने को समाज के लिए प्रेरक उदाहरण बताया। रामकथा के दौरान मोरारी बापू ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत और सार्वभौम है।

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यपालों पर स्टालिन ने साधा निशाना

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने नए साल के पहले विधानसभा सत्र के दौरान अपने–अपने राज्य सरकारों द्वारा तैयार भाषण न पढ़ने के लिए गुरुवार को तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यपालों पर तमकर निशाना साधा और कहा कि उनका रवैया स्पष्ट और जानबूझकर है। श्री स्टालिन ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यपालों पर विधिवत तरीके से चुनी हुई सरकारों को कमजोर करने और पार्टी एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने केरल और कर्नाटक के राज्यपालों द्वारा विधानसभा में राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ने से इनकार करने का जिक्र करते हुए कहा कि एकमात्र समाधान यह

है कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ नए साल के पहले विधानसभा सत्र को शुरू करने की इस पुरानी और अप्रासंगिक प्रथा को समाप्त किया जाए।श्री स्टालिन ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 20 जनवरी को विधानसभा सत्र के पहले दिन द्रमुक सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को देने से बचने और अपने अभिभाषण शुरू होने से पहले राष्ट्रगान न गाए जाने का हवाला देते हुए सदन से बाहर चले जाने के बाद अपने पहले के रुख को दोहराते हुए कहा कि द्रमुक देशभर में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों से परामर्श करेगी और इस पुरानी और अप्रासंगिक प्रथा को समाप्त करने के लिए अगले ही संसदीय सत्र में संवैधानिक संशोधन करेगी। उन्होंने कहा, ष्पहले तमिलनाडु फिर केरल अब कर्नाटक। यह रवैया जान–बूझकर अपनाया जा रहा है। राज्यपाल राज्य सरकारों द्वारा तैयार भाषण पढ़ने से इनकार कर रहे हैं और पार्टी एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विधिवत चुनी हुई राज्य सरकारों को कमजोर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब एकमात्र समाधान पहले वार्षिक विधानसभा सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू करने की प्रथा को समाप्त करना है। उन्होंने जोर दिया कि द्रमुक पूरे देश में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों से परामर्श करेगी तथा इस पुरानी और अप्रासंगिक प्रथा को समाप्त करने के लिए अगले ही संसदीय सत्र में संवैधानिक संशोधन करेगी।

संपादकीय

रोने से कुछ हासिल नहीं होगा

पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि चीन ने गैर–बाजार नीतियों पर चलते हुए फ्री मार्केट अर्थव्यवस्थाओं को अपने सस्ते उत्पादों से पाट दिया है। इस कारण वहां के उद्योग–धंधों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हैं। मगर हल क्या है? साल 2025 में चीन से व्यापार में भारत का घाटा रिकॉर्ड 116.12 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल भारत का निर्यात 5.5 प्रतिशत बढ़ते हुए 19.75 बिलियन डॉलर पहुंच गया, लेकिन चीन से आयात 12.8 फीसदी बढ़ कर 135.87 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। 2024 में चीन से भारत का व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर था। इन आंकड़ों ने देश में फिर बेचौनी पैदा की है। मगर ऐसा नहीं लगता कि इसकी बुनियादी वजहों पर कोई ऐसी ठोस चर्चा होगी, जिससे समाधान की तरफ बढ़ने में मदद मिले। ऐसी चर्चा के लिए चीन की निर्यात क्षमता के गंभीर आकलन की जरूरत होगी। 2025 में चीन ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार लाभ कमाया, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ऐसा अमेरिका के लिए निर्यात में 20 प्रतिशत गिरावट के बावजूद हुआ। उसने यूरोप, अफ्रीका, आसियान समूह और भारत जैसे देशों में बड़ी मात्रा में निर्यात बढ़ाने में कामयाबी पा ली। इस तरह उसने अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका के व्यापार युद्ध से अप्रभावित बनाए रखा है। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने इसका कारण उसकी अत्यधिक उत्पादन क्षमता एवं देश के अंदर कम उपभोग को बताया है। कहा है कि चीन ने गैर–बाजार नीतियों पर चलते हुए फ्री मार्केट अर्थव्यवस्थाओं को अपने सस्ते उत्पादों से पाट दिया है। इस कारण वहां के उद्योग–धंधों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हैं। मगर हल क्या है? पश्चिमी देश अपने यहां मजदूरी महंगी होने को समाधान के रास्ते में बाधा बताते हैं। मगर भारत जैसे देश पर तो यह बात लागू नहीं होती। भारत में औसत मजदूरी चीन से छह गुना सस्ती है। यह भारत के लिए लाभ का पहलू है। फिर भी भारत को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर का महंगा एवं अपर्याप्त होना, अनुसंधान पर न्यून खर्च, और कुशल कर्मियों का अभाव है। साथ ही उद्योग घरानों की कायम हुई मोनोपॉली या कार्टेल बनाने की उनकी प्रवृत्तियों ने बाजार में प्रतिस्पर्धा कुंद कर रखी है। इन मसलों का हल भारतीय नीति–निर्धारकों को ही ढूंढना होगा। चीन से आयात–निर्यात के आंकड़ों पर साल–दर– साल रोने से कुछ हासिल नहीं होगा।

दुनिया के लिए प्रेरक बनता भारत का चुनावी तंत्र

उमेश

स्वाधीनता के बाद जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया, वह हमारी अपनी नहीं, पश्चिम से आयातित है। दिलचस्प है कि आज यही व्यवस्था दुनियाभर में शासन की बेहतर प्रणाली के रूप में स्वीकार्य है। इसकी बुनियाद में इंग्लैंड की सन् 1215 में हुई मैग्नाकार्टा

की संधि है। आज का लोकतंत्र इसी संधि से निकले कानूनों और परंपराओं से विकसित हुआ है। जबकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल में भारतीय दिलों की पारंपरिक लोकतांत्रिक सोच है। दुर्भाग्य से भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की महत्ता को दुनिया हाल तक स्वीकार करने से हिचकती रही है। ऐसे माहौल में अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक एवं चुनावी सहायता संस्थान की अगुआई भारत को मिलना मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी में इस संस्थान को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी आईडीईए के नाम से जाना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय लोकतंत्र की अहमियत वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हो रही है। वैश्विक लोकतांत्रिक परिदृश्य के लिहाज से भारत को मिली अगुआई ऐतिहासिक है। 1995 में 14 देशों द्वारा स्थापित इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या अब 37 हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान स्थायी पर्यवेक्षक के तौर पर इस संगठन में शामिल हो चुके हैं। करीब आठ अरब जनसंख्या वाली दुनिया के करीब दो अरब बीस करोड़ पंजीकृत मतदाता इसी संगठन के सदस्य देशों के पास हैं। जिसमें भारत की हिस्सेदारी 99 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। आंकड़ों से साफ है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। इस लिहाज से देखें तो भारत की अध्यक्षता उसके लिए औपचारिक दायित्व से कहीं ज्यादा वैचारिक नेतृत्व का अवसर हो सकती है। इस संगठन में सदस्य देशों के चुनाव आयोग या चुनाव कराने वाली संस्थाएं ही शामिल होती हैं, लिहाजा भारतीय चुनाव आयोग इस संस्था का सदस्य है। जाहिर है कि इसी नाते अध्यक्षता भी आयोग के ही पास है। जिस वक्त घरेलू मोर्चे पर भारतीय चुनाव प्रणाली और मशीनरी सवालों के घेरे में है, उसी वक्त भारतीय चुनाव आयोग को इस प्रतिष्ठित संस्था की अगुआई मिली है। घरेलू मोर्चे पर विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग पर कभी वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है तो कभी नकारा बताया जाता है। ऐसे वातावरण में चुनाव आयोग को आईडीईए की अध्यक्षता मिलना सामान्य बात नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली की वैश्विक स्वीकृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दुनिया अब तक लोकतंत्र को "पश्चिमी मॉडल" के चश्मे से ही देखती रही है। जबकि इसके मूल में लोकतांत्रिक आत्मा नहीं, बाजार केंद्रित राजनीतिक ढांचा है, जहां व्यक्ति की बजाय संस्थाओं की स्वाधीनता और संसदीय परंपराओं पर जोर है। संचार और सूचना क्रांति एवं आर्थिक बदलावों के चलते आज का मतदाता बेहद जागरूक हो चला है। वह अपनी निजी राय की अहमियत की भी चाहत रखता है। इस वजह से पश्चिमी मॉडल वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सोच बदली है। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था अगर तनकर खड़ी है, तो उसके पीछे इन वैचारिक बदलावो का बड़ा योगदान है। एक अरब की भारी–भरकम मतदाता संख्या वालेभारतीय चुनावी तंत्र में भागीदारी बढ़ना मामूली बात नहीं है। इसे भारतीय चुनावी तंत्र की लचीली किंतु मजबूत व्यवस्था की सफलता के रूप में भी देखा जाना चाहिए। भारतीय चुनावी प्रबंधन में बढ़ते नवाचार, डिजिटल चुनावी प्रबंधन पर जोर, दिव्यांग और दूरस्थ मतदाताओं तक बढ़ती पहुँच, के लिए चुनाव आयोग की सोच ज्यादा जिम्मेदार है। चुनावी साक्षरता बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने जितने प्रयोग किए हैं, वैसा उदाहरण कहीं और नहीं दिखता। विपक्षी सवालों के बावजूद चुनावों में अगर मतदाता भागीदारी बढ़ी है, तो माना जा सकता है कि चुनाव आयोग के प्रति भरोसा कम नहीं हुआ है। इस लिहाज से देखें तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहुंच पुस्तकालयों और विमर्श के संस्थागत मंचों की बजाय बूथ और अंतिम व्यक्ति तक बढ़ी है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग की अध्यक्षता में 21 से 23 जनवरी के बीच आईडीईए देशों के चुनाव प्रमुखों और अधिकारियों की होने जा रही बैठक बेहद अहम हो जाती है। माना जा रहा है कि आयोग से दुनियाभर के अधिकारी जानना चाहेंगे कि मतदाताओं की भारी संख्या के बावजूद आयोग उन तक कैसे पहुंचता है और चुनाव प्रणाली की पवित्रता कैसे बरकरार है। चुनावी पवित्रता की नाभि–नाल पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़ी है। प्राचीन भारत का बज्जि गणतंत्र आधुनिक प्रणाली से कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक और लोकोन्मुखी था। दक्षिण भारत के दसवीं सदी के चोल शासकों ने ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था अपना रखी थी, उसे आधुनिक राजनीति विज्ञानी भी बेहतरीन प्रणाली मान रहे हैं। मैग्नाकार्टा के कुछ साल पहले कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर ने जिस अनुभव मंडपम् की स्थापना की थी, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे और एक परिणति तक पहुंचते थे। राजनीति शास्त्री इसे आधुनिक संसद का प्रथम स्वरूप मानते हैं। आज हमारी चुनाव प्रणाली मजबूत है तो इसकी एक वजह हमारी यह परंपरा भी है। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं। जिनके लिए भारत का अनुभव प्रेरक हो सकता है। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के लिए ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार और साइबर हस्तक्षेप, चुनावी धन में पारदर्शिता की कमी एवं युवाओं की घटती रुचि खतरा बन रही हैं। इसमें जनमत को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल ने कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनावी लिहाज से अपने सफल मॉडल आधारित अनुभव से लोकतांत्रिक राष्ट्रों की चुनाव प्रणाली के लिए प्रेरक हो सकता है। भारत को इन देशों की अगुआई इस बात का भी प्रतीक है कि हमारे लोकतंत्र की ताकत सिर्फ चुनाव में नहीं, बल्कि हर वोट को मिली अहमियत से है। इसी वजह से विविधरंगी समाज, भाषा, धर्म और असमानता के बावजूद भारतीय चुनाव प्रणाली शांतिपूर्ण बनी हुई है। साफ है कि विशाल और बहुलवादी समाज भारतीय लोकतंत्र की बाधा नहीं, ताकत है।

नाम है बोर्ड पीस मगर इसने दुनिया भर के नेताओं के मन की शांति छीन ली है

नीरज

दुनिया की कूटनीति एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमने लगी है। इस बार कारण है उनका नया और विवादास्पद प्रस्ताव बोर्ड ऑफ पीस। देखा जाये तो इस बोर्ड के नाम में भले पीस शब्द हो लेकिन इसने दुनिया भर के नेताओं के मन में अशांति पैदा कर दी है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने इस प्रस्ताव को गाजा में स्थायी युद्धविराम, पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक शांति की निगरानी के लिए पेश किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बोर्ड अब केवल गाजा तक सीमित नहीं रहा। यह पहल धीरे धीरे एक ऐसे वैश्विक मंच का रूप ले रही है जो संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को सीधी चुनौती देती दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप की बीस सूत्रीय गाजा शांति योजना का केन्द्रीय स्तम्भ है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए दुनिया भर के दर्जनों देशों को न्योता दिया गया है। खास बात यह है कि ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए न्यूनतम एक अरब डॉलर का योगदान अनिवार्य होगा। यानी शांति में भागीदारी अब नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आर्थिक हैसियत से तय होगी। अब तक मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने की हामी भरी है। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने इस पहल को समर्थन देने का संकेत दिया है। इनके अलावा कुछ अफ्रीकी और मध्य एशियाई देशों ने भी भागीदारी के संकेत दिए हैं। इन देशों का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र की जटिल और धीमी प्रक्रियाओं के मुकाबले ट्रंप का मॉडल तेज और निर्णायक साबित हो सकता है। मगर यूरोप में इस बोर्ड को लेकर तस्वीर बिल्कुल उलटी है। फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया जैसे देशों ने साफ शब्दों में कहा है कि वह किसी ऐसे मंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की वैधता को कमजोर करे। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश खुले तौर पर विरोध नहीं कर रहे लेकिन वह भी इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में हैं। इस तरह यूरोप दो खेमों में बंटता नजर आ रहा है, एक खेमा इसे अमेरिका केंद्रित शक्ति प्रदर्शन मानता है तो दूसरा इसे व्यावहारिक समाधान के रूप में देखने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत का रुख अब तक संतुलित और सावधान रहा है। भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण जरूर मिला है लेकिन नई दिल्ली ने अभी तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं दी है। भारत परंपरागत रूप से संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थक रहा है। भारत इस बात का आकलन कर रहा है कि यह बोर्ड वास्तव में शांति का माध्यम बनेगा या केवल राजनीतिक दबाव और प्रभाव का नया औजार। इसी बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना देता है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका में फ्रीज रूसी संपत्तियों में से एक अरब डॉलर बोर्ड ऑफ पीस को दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह रकम गाजा में युद्धविराम और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पुतिन ने यह भी कहा कि बाकी फ्रीज संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद वहां के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है। देखा जाये तो पुतिन का यह प्रस्ताव केवल उदारता नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल, अमेरिका में रूस की चार से पांच अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज है जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण की जरूरतों के सामने नगण्य है। पुतिन का असली उद्देश्य ट्रंप को यह संदेश देना है कि रूस टकराव नहीं बल्कि सौदेबाजी चाहता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब ट्रंप रूस और यूक्रेन दोनों पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप लगा चुके हैं और रूस के व्यापारिक साझेदारों पर नए प्रतिबंधों की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन ने साथ ही यह भी कहा है कि अमेरिका की अगुवाई वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने पर कोई भी फैसला रणनीतिक साझेदारों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। पुतिन ने बताया है कि रूस को भेजे गए प्रस्ताव में पश्चिम एशिया में समझौते, फिलस्तीन के लोगों की समस्याओं के संभावित समाधान खोजने तथा गाजा पट्टी में सबसे गंभीर मानवीय संकट को हल करने जैसी बातें प्रमुख हैं। उन्होंने कहा, श्इस संदर्भ में, मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना चाहूंगा। अहम बात यह है कि पूरी प्रक्रिया फिलस्तीन–इजराइली संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली हो और यह संयुक्त राष्ट्र के संबंधित निर्णयों के आधार पर हो।'' देखा जाये तो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस दरअसल शांति से ज्यादा शक्ति की राजनीति का नया प्रयोग है। यह पहल यह साफ करती है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में शांति भी

अब बाजार के नियमों पर चलेगी। जिसके पास पैसा है वही शांति की मेज पर बैठेगा और जिसके पास पैसा नहीं वह केवल फैसलों का पालन करेगा। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सार्वभौमिकता रही है। वहां छोटे और बड़े देश एक ही मंच पर खड़े होते हैं। ट्रंप का बोर्ड इस अवधारणा को उलट देता है। यहां स्थायी सदस्यता धन से खरीदी जा सकती है। यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से हटाकर खुले सौदेबाजी के रास्ते पर ले जाता है। यूरोप का विरोध इसी डर से पैदा हुआ है। फ्रांस और नॉर्डिक देशों को आशंका है कि अगर बोर्ड ऑफ पीस को वैधता मिल गई तो संयुक्त राष्ट्र केवल एक औपचारिक संस्था बनकर रह जाएगी। इसके उलट मध्य पूर्व के कई देश इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मंच के जरिये वे सीधे अमेरिका के साथ अपने हित साध सकते हैं भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है। एक ओर वह वैश्विक मंचों पर बड़ी भूमिका चाहता है तो दूसरी ओर वह किसी ऐसे ढांचे का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करे। भारत का झुकाव फिलहाल प्रतीक्षा और मूल्यांकन की नीति की ओर दिखता है। रूस की भूमिका इस पूरे खेल को और खतरनाक बना देती है। पुतिन बोर्ड ऑफ पीस को शांति मंच से ज्यादा सौदेबाजी के मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका प्रस्ताव यह दिखाता है कि वह फ्रीज संपत्तियों को भी कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार हैं।

कांग्रेस को असम से बहुत उम्मीदें

अजीत द्विवेदी

अप्रैल में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें से दो राज्य कांग्रेस की उम्मीदों के प्रदेश हैं। कांग्रेस को केरल और उसके साथ साथ असम से बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि 10 साल की सत्ता ने प्रदेश में भाजपा को अलोकप्रिय बनाया है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के भड़काऊ भाषणों व विभाजनकारी राजनीति से लोग ऊबे हुए हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? यह सही है कि 10 साल की एंटी इन्कम्बैंसी है और संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए से भी असम के लोगों में नाराजगी है। फिर भी पिछले दो चुनावों से जिस स्तर का ध्रुवीकरण हो रहा है वह कांग्रेस के लिए चुनौती है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने बदरूद्दीन अजमल की पार्टी से तालमेल नहीं किया है। इससे ध्रुवीकरण की संभावना थोड़ी कम हुई है। बहरहाल, पहले सीएए की बात करते हैं। भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए पर अमल इसलिए रोक दिया था क्योंकि असम में उसको इसके नुकसान का अंदाजा हो गया था। गौरतलब है कि सीएए का कानून 2019 में पास किया गया लेकिन उसे लागू करने के नियम नहीं बनाए गए। 2021 के चुनाव में भाजपा को इसका असम में फायदा हुआ और पश्चिम बंगाल में थोड़ा नुकसान हुआ। अब पश्चिम बंगाल में फायदे के लिए उसने सीएए लागू कर दिया लेकिन हो सकता है कि असम में इसका नुकसान हो। असम में यह धारणा बनी है कि सीएए से बांग्ला बोलने वाली आबादी बढ़ जाएगी और असमिया भाषा व संस्कृति कमजोर होगी। कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री पद के अघोषित दावेदार गौरव गोगोई अहोम वंश से जुड़े हैं और असमिया भाषा और संस्कृति के मुद्दे उठाते रहते हैं। साथ ही कांग्रेस ने भाषा व संस्कृति के आधार पर सीएए का विरोध करने वाले समूहों द्वारा बनाई गई पार्टियों से तालमेल किया है। वह भाजपा के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण के मुकाबले भाषा और अस्मिता के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने असम में उम्मीदवारों का चयन करने के लिए छंटनी समिति बनाई है, जिसका अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाया गया है। इससे भी लग रहा है कि कांग्रेस असम को लेकर काफी भरोसे में है। गठबंधन की बातचीत भी लगभग तय है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने के लिए कांग्रेस ने इस बार बदरूद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एआईयूडीएफ से तालमेल नहीं किया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अजमल की पार्टी के लिए 20 सीटें छोड़ी थीं। पिछली बार की तरह इस बार बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ भी कांग्रेस के साथ नहीं है। हागरामा मोहिलारी की पार्टी ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी का चुनाव जीता और उसके बाद भाजपा ने उससे तालमेल कर लिया है। अब बोडोलैंड की दोनों पार्टियां बीटीसी और यूपीपीएल भाजपा के साथ हैं। कांग्रेस ने अजमल और मोहिलारी की पार्टी को 32 सीटें दी थीं और खुद 95 सीटों पर लड़ी थी। इस बार ये दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस ने अलग अलग जातीय समूहों में असर रखने वाली छोटी पार्टियों के साथ अपना गठबंधन किया है। कांग्रेस ने पिछली बार महाजोत बनाया था, जिसमें एआईयूडीएफ, बीपीएफ के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, तीन कम्युनिस्ट पार्टियां और एक अन्य दल शामिल था। इस बार कांग्रेस ने असोम सम्मिलितो मोर्चा बनाया है। इसमें कांग्रेस के अलावा पहले की तरह सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले शामिल है। पिछली बार यूआरएफ बना कर अलग चुनाव लड़ी दो स्थानीय पार्टियों लुरिनजोत गोगोई की असम जातीयता परिषद और अखिल गोगोई की रायजोर दल से इस बार कांग्रेस ने तालमेल किया है। इनके अलावा ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस से भी कांग्रेस ने तालमेल किया है। यूपीपीएल और बीपीएफ के नहीं होने से हिल एरिया के लिए कांग्रेस को एक पार्टी की जरुरत थी। सात पार्टियों का सम्मिलित मोर्चा भले पिछली बार के मुकाबले कमजोर दिख रहा है लेकिन जमीनी असर और नैरेटिव के मामले में इस मोर्चे ने चुनाव से पहले भाजपा को कड़ी टक्कर देने का संकेत दिया है। अब अगर पिछले चुनाव की बात करें तो एनडीए और महाजोत के बीच बेहद करीबी मुकाबला हुआ था। एनडीए को 44.51 फीसदी वोट मिला था तो महाजोत को 43.68 फीसदी वोट मिला था। यानी अंतर एक फीसदी से भी कम था। हालांकि सीटों में बड़ा अंतर आ गया था।

25 वर्षों के भारत चित्र की असलियत

हरिशंकर व्यास

इक्कीसवीं सदी के पहले पच्चीस वर्ष। ये ढाई दशक मानवता की अमूल्य, अविस्मरणीय अवधि के थे। इसमें मनुष्य के हाथों मनुष्य–समतुल्य कृत्रिम बुद्धि (एआई) बनी तो अंतरिक्ष–ब्रह्माण्ड को भेदने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना। तब पृथ्वी के सर्वाधिक आबादी वाले भारत में क्या बना? भीड़ और उसकी आवाजाही या कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसी से फैला बाजार! ध्यान रहे बीसवीं सदी के आखध्रि दशक में पीवी नरसिंह राव नाम का प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त हुआ था। वह बुद्धि और दृष्टि लिए हुए था। सो, उन्होंने नौकरशाहों के समाजवाद (पूंजी, कोटा–परमिट) से भारत को मुक्त कराया। मंत्रालयों में पूंजी, उद्यम, पुरुषार्थ के चक्कर खत्म (घटाए) कराए। उन दिनों चीन में देंग शियाओ पिंग ने जहां देशी–विदेशी पूंजी, शिक्षा–ट्रेनिंग, मेहनत से देश को गढ़ने में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को धार दी थी तो नरसिंह राव–मनमोहन सिंह ने भी भारत में अवसर खोले थे। राव सरकार ने बतौर मानव संसाधन लोगों को समर्थ बनाने के फैसले लिए। हालांकि उनसे पहले वीपी सिंह ने मंडल–मस्जिद में समाज को भीड़ बनाने के विषाणु फैला दिए थे। तभी लालू यादव, मुलायम सिंह, लालकृष्ण आडवाणी की आरक्षण, धर्म की आग फैली थी। उसी का असर था जो इक्कीसवीं सदी की मिलेनियम पीढ़ी की दिशा बिगड़ी। नौजवान या तो आईटी क्षेत्र के बैक–ऑफिस, कुलीगिरी की तरफ दौड़े या आरक्षण की भूख में अंधे होकर सरकारी नौकरी की माया में भटके। मेरा मानना है समाज के भटकने के संग अर्धसाक्षरता की शिक्षा का अटल बिहारी वाजपेयी–डॉ. मुरली मनोहर जोशी का सर्व शिक्षा अभियान वह दूसरा मोड़ था, जिससे पहली कक्षा से बारहवीं तक की शिक्षा से मिलेनियम पीढ़ी की बरबादी बनी। सरकारी स्कूलों का भत्र्हा बैठा। प्राइवेट शिक्षा से शिक्षा–असमानता बनी। शिक्षा का कुल नतीजा बुद्धिविहीन आईटी कुलियों, सरकारी नौकरियों की भूख, कुशलता–कौशल के नाम पर बेगार करती नौजवानों की भीड़ थी। न खेती व परंपरागत कौशल में प्रवीण और न पहले जैसे काबिल इंजीनियर–डॉक्टरों का शिक्षण। सो, जेनरेशन दुकान, गुमटी, धंधों में खपी। इसी के ट्रेंड को बूझ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला था कि दफ्घ्तर के बाहर पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। मतलब नरसिंह राव–मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी का बेसिक फक ‘यह भी है जो राव–वाजपेयी–मनमोहन सिंह ने भूमंडलीकरण, वैश्विक ट्रेंड में उत्पादकता, औद्योगिक उत्पादकता, आईटी–सेवा क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनवा इक्कीसवीं सदी के सिनेरियो में दिमाग खपाया। वही नरेंद्र मोदी ने चाय–पकौड़े की गुमटी यानी व्यापार, धंधा, मुनाफे में भारत का भविष्य बूझा है। यह उनका दोष नहीं है। गुजरात की तासीर में विकास मतलब व्यापार, धंधा, दुकान, वाणिज्य से मुनाफे की सर्वोच्चता से ही सब है। इसी कारण अंबानी–अडानी प्रतिमान हैं। बाकध्ी सब जाएं भाड़ में और धंधा, मुनाफा ही परम पुरुषार्थ। सोचें, पिछले तीन वर्षों में अंबानी–रिलायंस ने यूक्रेन संकट में रूस से सस्ता–कच्चा तेल खरीद उसे देश–दुनिया को कितना महंगा बेचा? अरबों–खरबों रुपए का मुनाफा कमाया होगा। अब यदि इस धंधे से भारत ट्रंप के टैरिफ का मारा है तो अंबानी–रिलायंस का तो कुछ नहीं बिगड़ना है। मगर देश, मोदी सरकार के लिए तो अंबानी सफलता की कहानी है! विषयांतर हो रहा है। मूल बात पर लौटें। भारत ने 1990 से 2000 के बीच अपने् इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की भूमिका बनाई। राव–मनमोहन सिंह ने हाईवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार व बिजली क्षेत्र को नौकरशाही जकड़न से मुक्त किया। निज पूंजी, उद्यम को स्वतंत्रता दी। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण शुरू हुआ तो उससे इक्कीसवीं सदी के 25 वर्षों की सतत कोशिश से भारत को क्या प्राप्त है? कह सकते हैं कनेक्टिविटी और बिजली का उजाला है। अर्थात हाईवे के नेटवर्क, संचार, आवाजाही–माल ढुलाई, ऊर्जा में सुगमता है। जैसा भी हो पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। ऐसा होनी मोदी सरकार से नहीं है। उसका योगदान सरकारों की निरंतरता की मौजूदा कड़ी के नाते है। संयोग था जो नरसिंह राव के सुधारों के बाद की सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभारी मंत्री कामकाजी हुए। वाजपेयी सरकार के भुवनचंद खंडूरी हों या कांग्रेस के कमलनाथ–सीपी जोशी या नितिन गडकरी से भारत हाईवे नेटवर्क में गुंथा गया है। इन सभी मंत्रियों ने नौकरशाही को सख्ती से कसते हुए काम निकालने की धुन में काम किया। ध्यान रहे कांग्रेस ने ही अडानी को पहला बंदरगाह दिया था। ऐसे ही उसने दक्षिण भारत की कंपनियों को हाईवे, एयरपोर्ट, बिजलीघर बनाने के काम सौंपे थे। सरकारों की प्राथमिकता से ही पच्चीस वर्षों का इंफ्रास्ट्रक्चर लेखा है। अब सवाल है कि जिस असल काम के लिए बुनियादी ढांचा बना उसका क्या हुआ? क्या भारत में कारखाने खुले, निर्यात बढ़ा? भारत की उत्पादकता बढ़ी? औद्योगिक क्रांति हुई? भारत आत्मनिर्भर बना? ऐसा न होना 25 वर्षों के भारत चित्र्ह की असलियत है। किसी भी अर्थशास्त्री से पूछें, किसी भी विकसित देश की गाथा पढ़ें तो मालूम होगा कि जब भी किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो उस देश में फैक्ट्रियां खुलीं, रोजगार बढ़ा। उत्पादकता बढ़ी। निवेश आया और निर्यात बढ़ा। उसी से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत निकली। 25 वर्षों में भारत में उलटा हुआ! औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। उलटे 140 करोड़ लोगों की भीड़ से भारत वह बाजार बना, जिसके हाईवे, बंदरगाहों, एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन ने चीन में बने सामान की माल ढुलाई को आसान बनाया। अंबानी–अडानियों को शॉपिंग मॉल बनाकर, बंदरगाह विकास कर चीन, वियतनाम से टरबाइन या सोलर मशीनरी आदि हर सामान लाकर भारत में खपाने, लगाने, बेचने का धंधा चोखा बना। सो, इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत का औद्योगिकीकरण नहीं है। मगर बाजार फैला है और लागत वसूली है। लोगों की कनेक्टिविटी बनी तो उसके साथ 140 करोड़ से ही टोल टैक्स, हवाई टिकट, फोन बिल की मनमानी वसूली का रिवाज–कायदा है। एयरपोर्ट–बंदरगाह क्षेत्र में अडानी और इंडिगो बने। फोन–संचार पर जियो–एयरटेल की एकछत्रता हुई। बिजली में अंबानी, अडानी सहित कोलकाता–हैदराबाद की पावर कंपनियों की सरकारी ढांचे के जरिए मनमानी बिजली रेट, बिल बने हैं। सन् 2000 से पहले भारतीयों के अनुभव में बिजली न होने या कटौती की शिकायत होती थी। अब घर–घर की शिकायत है कि बिजली–पानी के कितने ज्यादा बिल आ रहे हैं। सो, उपयोग और कंपनियों की कमाई का वह चक्र है, जिसमें न सस्ता है न स्वदेशी है और न स्वावलंबी भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तमाशा है। नतीजतन एक्सप्रेस वे, हाईवे, स्टेट रोड आदि की दशा, इनके किनारे वही दशा है जो 2000 से पहले पटना से मुजफ्फरपुर जाते वक्त थी। एक उदाहरण बिहार के हाईवे का है।

15 साल सेवा के बाद बेरोजगार हुए आउटसोर्स कर्मी, अपर मुख्य सचिव से लगाई न्याय की गुहार

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में कंपनी बदलते ही आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाने का विरोध तेज होने लगा है। करीब 15 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार हुए ये कर्मी बृहस्पतिवार को लखनऊ पहुंचे और अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष से मुलाकात कर उन्हें पीड़ा सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। आजमगढ़ से आए करीब 110 कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक दुर्गा प्रसाद के साथ अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के समय जिन लोगों की जमीन ली गई थी उनके परिजनों को वर्ष 2009 से 2012 के बीच आउटसोर्सिंग के जरिये कॉलेजों में सुरक्षाकर्मी, वॉर्डब्वाय, ट्रॉली मैन, मरीज सहायक के पदों पर नौकरी दी गई थी। सरकार ने भी 19 मार्च 2025 को जारी आदेश में कहा था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद भी नए टेंडर में करीब 110 पद कम कर दिए हैं। प्राचार्य प्रो. वीरेंद्र राव का कहना है कि सुरक्षा कर्मी के पद पर सैनिक कल्याण बोर्ड से रखने का आदेश है। इससे कुछ लोगों को हटाया गया है। इसी तरह कन्नौज, बदायूं, सहारनपुर से आए आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी मनमानी तरीके से हटाने का आरोप लगाया। शासन ने 19 मार्च 2025 को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को जारी आदेश में कहा था कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों, हृदय रोग संस्थान व जेके कैंसर संस्थान कानपुर, नर्सिंग कॉलेज कानपुर, पैरामेडिकल कॉलेज झांसी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के अलावा 2044 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। इन्हें उप्र पूर्व सैनिक कल्याण निगम से तैनात किया जाए। आरोप है कि कॉलेज प्राचार्यों ने अतिरिक्त भर्ती के बजाय पहले से स्वीकृत पदों में ही कुछ लोगों को निकाल दिया और सैनिक कल्याण निगम से पूर्व सैनिकों को रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि कुछ लोग मिले थे। शिकायती पत्र दिया है। संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली जा रही है।

रात को शराब पीने के बाद दोस्तों में हुआ विवाद

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को नहर की पटरी के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। लोगों ने देखा तो मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना नगराम थाना क्षेत्र के गुलाल खेड़ा गांव के पास की है। यहां शारदा नहर हैदरगढ़ शाखा की बाईं पटरी के पास ओमप्रकाश (22) का शव पड़ा मिला। वह गुलाल खेड़ा का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, गुरुवार की रात साथियों संग शराब पी गई। इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है।

संक्षिप्त खबरें

तीन दिन तक मुख्यालय को नहीं भेजी रिपोर्ट बढ़ सकती हैं अफसरों की मुश्किलें

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के झांसी में कारोबारियों से घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार सेंट्रल जीएसटी के अफसरों की वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत थी। छापे के बाद डिप्टी कमिश्नर और दोनों अधीक्षकों ने इसी वजह से बरामद दस्तावेजों को कार्यालय में जमा नहीं कराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को छापे से संबंधित रिपोर्ट तक नहीं भेजी थी। सीबीआई की पूछताछ में अधीक्षक अनिल कुमार तिवारी और अजय कुमार शर्मा ने स्वीकार किया कि छापे की कार्रवाई करोड़ों रुपये की उगाही के उद्देश्य से की गई थी। रिमांड के दौरान उनसे उनके घरों से बरामद नकदी और चांदी को लेकर भी सवाल किए गए। दोनों ने बताया कि वकील नरेश कुमार गुप्ता के जरिए उनका संपर्क कारोबारियों से हुआ था, जिसने मामला निपटाने के लिए 1.50 करोड़ रुपये घूस दिलाने का भरोसा दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी ने छापे से जुड़ी जानकारी मुख्यालय को न देने के निर्देश दिए थे। सीबीआई शुक्रवार को भी दोनों से पूछताछ करेगी।

चल–अचल संपत्ति का ब्योरा न देने पर रुकेगा वेतन शिक्षक

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है। ऐसा न करने पर उनका फरवरी का वेतन रुक जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं।उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देश के क्रम में सभी अधिकारियों–कर्मचारियों को अपनी चल–अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है। जो कार्मिक ब्योरा देंगे उनका ही वेतन फरवरी में जारी किया जाएगा।

पांच दिवसीय बैंकिंग के समर्थन में रैली

लखनऊ, (संवाददाता)। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को हजरतगंज स्थित एसबीआई मुख्य शाखा से रैली निकालकर सभा की। 27 जनवरी तक मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बैंककर्मियों ने मांग के समर्थन में कई धरना–प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया, लेकिन केंद्र सरकार एक मांग को भी मानने पर तैयार नहीं है। लक्ष्मण सिंह ने कहा, रिजर्व बैंक, एलआईसी, सेबी, नाबार्ड, राज्य सरकार, एनपीसीआई आदि में पांच दिन काम हो सकता है तो बैंक में क्यों नहीं। सभा को एसके संगतानी, आरएन शुक्ला, संदीप सिंह, एसडी मिश्रा, ललित श्रीवास्तव, प्रभाकर अवस्थी, राकेश पांडेय ने भी संबोधित किया। मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि मांग न पूरी होने पर 27 को देशव्यापी हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मी हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक में सभा व प्रदर्शन करेंगे।

प्रदेश के हर विकासखंड में प्रवेश का तय होगा लक्ष्य

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निर्धारित सीटों के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम 1.41 लाख सीटों पर ही पिछले साल प्रवेश हुआ है। ऐसे में नए सत्र 2026–27 में हर विकास खंड में जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रवेश कराने का लक्ष्य निर्धारित कर उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के बच्चों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। इसके लिए हर निजी स्कूल में पूर्व प्राथमिक व कक्षा एक में कुल क्षमता का 25 फीसदी सीटें तय हैं। नए सत्र 2026–27 में मैप 68 हजार स्कूलों के सापेक्ष लगभग 6.80 लाख सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए दो फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि नए सत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के आधार पर नामांकन के लिए बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इसमें बीएसए, बीईओ व बाल विकास परियोजना अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव–गांव प्रचार–प्रसार कराएं। उन्होंने आरटीई में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आय, निवास, जाति व दिव्यांग प्रमाणपत्रों को बनाने की प्रक्रिया जिला, तहसील व ब्लॉक स्तर पर सुगम बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में आवेदन के लिए सहायता केंद्र भी शुरू करने के निर्देश दिए।

दावोस में एस्सार समूह के साथ 25 हजार करोड़ का एमओयू

लखनऊ, (संवाददाता)। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के चौथे दिन दावोस में उत्तर प्रदेश सरकार और एस्सार समूह के बीच 25 हजार करोड़ रुपये का समझौता (एमओयू) हुआ। इस निवेश से राज्य में पावर और ऊर्जा प्रणालियों, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और डाटा सेंटर जैसे क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस साझेदारी से प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, सप्लाई चेन अधिक प्रभावी बनेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एसए टेक्नोलॉजीज ने इन्वेस्ट यूपी के साथ 200 करोड़ रुपये का करार किया है। इसके तहत राज्य में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा।वहीं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए गैर–वित्तीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास के प्रति प्रदेश की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दावोस में गूगल, ब्लैकरॉक, बीसीजी, एचसीएल टेक, इंडियन ऑयल, टॉपसो, इलेवनलैब्स, आरएमजेड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई वैश्विक कंपनियों और संगठनों के साथ निवेश और सहयोग को लेकर संवाद हुआ।

संक्षिप्त खबरें

न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन की घोषणा की मांग पर धरना

लखनऊ, (संवाददाता)। बजट में न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन की घोषणा की मांग को लेकर पेंशनरों ने बृहस्पतिवार को गोमतीनगर स्थित ईपीएफ कार्यालय के समक्ष धरना दिया। ईपीएस–95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के धरने में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व श्रम मंत्री के आश्वासनों के बावजूद पेंशन नहीं बढ़ रही है। राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनानगर ने बताया कि सरकार कई योजनाओं में बिना किसी अंशदान के चार हजार रुपये तक पेंशन बांट रही है। उधर, ईपीएस–95 के पेंशनरों को 35 साल के सेवा में नियमित पेंशन अंशदान ईपीएफओ में जमा करने के बावजूद औसतन 1171 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही। ईपीएफओ आयुक्त अश्विनी कुमार को श्रम मंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। एस. तिवारी, राजीव भटनागर, राजशेखर नागर, आरएन. द्विवेदी, नासिर खां, पीके श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। प्रदर्शन में रोडवेज आवश्यक वस्तु निगम, अपट्रॉन, एचएएल, आईटीआई, सीड कॉर्पोरेशन, एफसीआई, वन निगम, निर्माण निगम और निजी संस्थाओं के पेंशनर शामिल हुए।

केजीएमयू के गेट पर बजाई बीन

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू के गेट नंबर–दो के सामने बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे अखिल भारतीय सपेरा महासभा के सदस्यों ने बीन बजाकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि संस्थान में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को समूह घ की नौकरी दी गई है। पुलिस ने सपेरों को परिसर में घुसने नहीं दिया। अध्यक्ष श्रीपतनाथ सपेरा ने कहा, एक ओर सपेरा समाज के हाईस्कूल, इंटर पास युवा तमाशा दिखाने पर मजबूर हैं तो दूसरी ओर वहीं रोहिंगयाओं को नौकरी दी जा रही है। केजीएमयू के कुछ अधिकारी हमारा हक मार रहे हैं। उधर, केजीएमयू अधिकारियों का कहना है कि सेवायोजन पोर्टल से संविदा पर नियुक्ति की जा रही है।

राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर गीत, संगीत और लोक कलाओं की समृद्ध प्रस्तुति

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर प्रदेश की विकास यात्रा के साथ–साथ गीत, संगीत और लोक कला की विविध प्रस्तुतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके लिए संस्कृति विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोजन में गांव से लेकर मण्डल स्तर तक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में चयनित कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेश की प्राचीन और आधुनिक लोक कलाओं, शास्त्रीय वाद्ययंत्रों और नाट्य परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता "हमारी संस्कृति–हमारी पहचान" (संस्कृति उत्सव 2025–26) के चयनित प्रतिभागियों को प्रदेश की लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंच प्रदान किया जा रहा है। इस बहुस्तरीय आयोजन में 14–25 वर्ष आयु वर्ग के किशोर और युवा कलाकार गायन, वादन, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोकनाट्य, सुगम संगीत, जनजातीय व लोक वाद्ययंत्र और काव्य पाठ जैसी विविध विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

यहां सपा कार्यालय खाली करने की नोटिस वापस, हाईकोर्ट ने निस्तारित की समाजवादी पार्टी की याचिका

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने सम्बंधी नगर पालिका परिषद की नोटिस को चुनौती देने वाली सपा की याचिका निस्तारित कर दी। बृहस्पतिवार को सुनवाई के समय सीतापुर नगर पालिका परिषद के वकीलों ने नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी का 22 जनवरी का आदेशध नोटिस, कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसमें कहा गया था कि याचिका में चुनौती दिए गए 7 जनवरी के आदेशध नोटिस को यह कहकर वापस ले लिया गया है कि समुचित नियमों के तहत करवाई की जाएगी। इसपर, कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई नई कारवाई होने पर, याची को इसे चुनौती देने की छूट होगी। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश समाजवादी पार्टी की याचिका पर दिया। याची की ओर से दलील दी गई थी कि नोटिस के अनुसार टाउन हॉल प्रांगण में जिस जमीन पर सपा कार्यालय बना हुआ है, वह नजूल की भूमि है। 15 जनवरी 2005 को इस भूमि को पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित किया गया था, हालांकि, आवंटन के चार महीने बाद ही 14 मई 2005 को इसका आवंटन निरस्त भी कर दिया गया था। दलील दी गई कि नोटिस तथ्यात्मक तौर पर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वर्ष 2005 में नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से 90 साल के पट्टे पर यह जमीन पार्टी कार्यालय बनाने के लिए दी गई थी। सपा कार्यालय 90 साल के लीज डीड के आधार पर बना है न कि 15 जनवरी 2005 के आवंटन के आधार पर। यह भी कहा गया था कि यदि 90 साल की लीज डीड निरस्त करनी है तो याची पक्ष को उसकी नोटिस तामील करायी जानी चाहिए। वहीं, नगर पालिका की ओर से पेश वकील का कहना था कि उन्हें याची पक्ष की ओर से किए गए इस दावे के संबंध में निर्देश(जानकारी) प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की थी।

पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने 17 शिकायतों पर की जनसुनवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने गुरुवार को इन्दिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त 17 शिकायतों और पत्रावलियों पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सभी मामलों का गंभीरता से अवलोकन किया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जनसुनवाई में कई महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विचार किया गया। आयोग ने पशु चिकित्साधिकारी के 404 पदों पर सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण शून्य किए जाने के मामले की गंभीरता से सुनवाई की और वर्ष 1994 के बाद की सीधी भर्तियों, आरक्षण स्थिति और रोस्टर रजिस्टर का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई। जगन्नाथ प्रसाद गंगवार को भूखण्ड न दिए जाने के प्रकरण में उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को पक्ष रखने हेतु बुलाया गया, लेकिन किसी सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, जिस पर अध्यक्ष ने अप्रसन्नता व्यक्त की। सोनू कश्यप हत्याकांड से संबंधित प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है।नीलम, प्रधानाध्यापिका, कानपुर देहात के प्रकरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। वहीं, विनोद कुमार के प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता 30वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग उपस्थित रहे और पिछड़े वर्ग के कार्मिक की समस्या का समाधान कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।शिवबदन राम के प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि लगभग छह वर्षों के उपरान्त जीपीएफ, सामूहिक बीमा और ग्रेच्युटी की 6 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। डॉ. गौरव नंद, कासगंज के प्रकरण में संबंधित अधिकारी ने बताया कि देयकों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा।

गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास ने थामी शहर की रफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के लिए बृहस्पतिवार को ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था। चारबाग से परेड निकली, जो विधान भवन के सामने से होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंची। पूर्वाभ्यास के दौरान शहर के बड़े हिस्से में वाहनों की रफ्तार थम गई। सुबह 10 से 12रू30 बजे तक जाम की स्थिति सबसे ज्यादा विकट रही। नेशनल कॉलेज के सामने जाम में एंबुलेंस फंस गई। चालक लगातार सायरन बजाता रहा। काफी देर बाद एंबुलेंस को रास्ता मिल सका। उधर, परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान हजरतगंज से एंबुलेंस आ गई जिसे परेड को रोककर रास्ता दिया गया। जगह–जगह पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। कैंट इलाके में सुबह 10 बजे से ही वाहनों की कतार लग गई। काफी देर तक लोग जाम में फंसे रहे। कैसरबाग, चारबाग, हुसैनगंज समेत कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुर्सी रोड पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से रैली निकाली जा रही थी। इसकी वजह से टेढ़ीपुलिया पर लंबा जाम लग गया। लोग वाहनों की कतार में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह जाम खुलवाया। जाम का असर पॉलीटेक्निक चौराहे और मुंशीपुलिया पर भी देखने को मिला। कमता इलाके में भी वाहन रेंगते नजर आए। गणतंत्र दिवस परेड का 24 जनवरी को फुल ड्रेस पूर्वाभ्यास होगा। उस दिन भी डायवर्जन लागू रहेगा। परेड चारबाग से निकलकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचेगी। 26 जनवरी को मुख्य आयोजन के दिन भी इसी प्रकार डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस शव वाहन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को निकलवाएगी।

प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण को बड़ी मजबूती, 14 जनपदों के 18 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का वर्चुअल लोकार्पण

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज पशुपालन निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 14 जनपदों में स्थापित 18 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन केन्द्रों के निर्माण से गोवंश संरक्षण की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि इन 18 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों में मिर्जापुर जनपद में तीन, बरेली और कानपुर देहात में दो–दो तथा आजमगढ़, कासगंज, उन्नाव, बुलन्दशहर, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुलतानपुर, फिरोजाबाद, रायबरेली और बदायूं में एक–एक केन्द्र का शत–प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन सभी केन्द्रों की कुल निर्माण लागत 28 करोड़ 82 लाख रुपये है और प्रत्येक केन्द्र में लगभग 400 गोवंश के संरक्षण की क्षमता विकसित की गई है।इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा–निर्देशन में प्रदेश सरकार गोवंश के भरण–पोषण, संरक्षण और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। गोआश्रय स्थलों और वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि निराश्रित गोवंश को सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त चारा, भूसा, प्रकाश और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं, ताकि गोशालाओं में किसी भी स्थिति में गाय भूखी न रहे।कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने संबंधित जनपदों के ग्राम प्रधानों, मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों और केयरटेकरों से संवाद करते हुए गोवंश के रखरखाव और स्थानीय सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि गो संरक्षण के कार्यों में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा केन्द्रों के संचालन और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 630 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनके सापेक्ष 421 केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 410 केन्द्र क्रियाशील किए जा चुके हैं। प्रत्येक वृहद गो संरक्षण केन्द्र की गोवंश धारण क्षमता 400 है तथा प्रति इकाई निर्माण लागत 160.12 लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रदेश में 0.5 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी गोआश्रय स्थल बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। निराश्रित गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अभूतपूर्व और उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण हेतु शत–प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से दिसंबर 2025 तक किया जा चुका है। गो संरक्षण कार्यक्रमों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक उन्नति के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6503 अस्थायी गो आश्रय स्थल, 421 वृहद गो संरक्षण केन्द्र और 259 कांजी हाउस, जबकि शहरी क्षेत्रों में 314 कान्हा गो आश्रय स्थल संचालित हैं।

ब्लैकआउट मार्कड्रिल के दौरान बिजली गुल होते ही गूंजती है सायरन,धमाके के बीच सुनाई देती है चीख पुकार

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।शुक्रवार की शाम 6रू00 बजते ही कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में अचानक हवाई हमले की सायरन सुनाई पड़ती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है।जिसको लेकर आसपास के स्थानीय लोगो मैं हड़कंप मच गया। उसके बाद धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है जिसमें कुछ लोगों की घायल होने और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस का सायरन भी लोग सुनते हैं इससे पहले वह कुछ भयभीत होते कि उन्हें बताया जाता है कि यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के 75 जिलों में शुक्रवार की शाम ब्लैक आउट

मार्कडिल था। बताते चलें शुक्रवार की शाम 5रू00 के बाद पुलिस ने सिविल लाइन के सभी मार्गो पर बेरिकेटिंग लगाकर थोड़ी देर के लिए आवागमन बंद कर दिया था और ठीक शाम 6:00 बजे अचानक सायरन बजते ही बिजली गुल हो जाती है और देखते ही देखते धमाके की आवाज और कई लोग सड़क पर घायल हो जाते हैं जिन्हें पूर्व से तैनात एसडीआरएफ फायर कर्मियों, पुलिस कर्मियों सहित अन्य पुलिस के विभिन्न शाखों में तैनात कर्मियों ने इन घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय पहुंचाया वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आज पर काबू पाया।इस संबंध मैं मौके पर तैनात एडीएम सिटी योगेंद्र पाण्डेय व एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी तथा सीएफओ एमपी सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि ब्लैक आउट मार्कडिल करने का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान लोगों को क्या करें क्या ना करें की प्रति जागरूक करना था। इस मौके पर कमांडेंट राघवेंद्र शुक्ला, अग्निशमन अधिकारी प्रदीप पांडेय, एआरटीओ प्रशासन डा आरपी सिंह, जिला सूचना अधिकारी अधीर रंजन के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

कल 25 जनवरी को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर अपर जिलाधिकारीध्उप जिला निर्वाचन अधिकारी परमानन्द झा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 25 जनवरी को 16वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी तहसील स्तर व समस्त मतदेय स्थलों पर कार्यक्रम होगा और मतदाता शपथ दिलाई जायेगी तथा नये

युवा मतदाता को ईपिक कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। मुख्य कार्यक्रम टी डी इन्टर कालेज में दिन में 11 बजे से आयोजित है। नगर के सभी इन्टर व डिग्री कालेज से छात्र छात्राएं अपने कालेज से मतदाता जागरूकता रैली लेकर बैनर के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल टी डी इन्टर कालेज पहुंचेगे, जहाँ पर मतदाता जागरूकता विषय पर रंगोली, मेहंदी व पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, तथा विजेताओं व उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूर्ण मनोयोग एंवम हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाय।

संक्षिप्त खबरें

मिशन शक्ति के तहत महिला एसओ ने किया जागरूक

अयोध्या। शनिवार को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ कैंट क्षेत्र में जाकर महिलाओ व लडकियो को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद महिलाओं तथा लड़कियों को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दिया।उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने

विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया। बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें,जरूरत पड़ने पर आपको यह नंबर कम देंगे।इस मौके पर उप निरीक्षक संजीव मिश्रा,महिला उप निरीक्षक श्वेता,ममता पाठक सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रही।

बिना पंजीकरण के चल रही थी क्लीनिक, 24 घंटे में कागजात पूरा करने के निर्देश

भदोही, (संवाददाता)। पुरानी बाजार में पानी टंकी के पास बिना पंजीकरण के एक साल से चल रही केपी विश्वास क्लीनिक पर जांच करने के लिए बृहस्पतिवार को सुरियावां अधीक्षक डॉ. अभिषेक नाग पहुंचे। अधीक्षक ने क्लीनिक का लाइसेंस मांगा, वहां पर तैनात कर्मचारी कागजात नहीं दिखा सके। अधीक्षक ने 24 घंटे के अंदर सीएमओ कार्यालय जाकर कागजात दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। चेताया कि ऐसा न करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। अधीक्षक ने बताया कि क्लीनिक संचालक लाइसेंस दूसरी जगह रखे जाने का बहाना बना रहा था।

वसंत पंचमी पर एक लाख श्रद्धालु करेंगे स्नान, घाटों पर 10-10 गोताखोर तैनात

भदोही, (संवाददाता)। माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व वसंत पंचमी पर चार प्रमुख घाटों पर करीब एक लाख लोगों के स्नान करने की संभावना जिला प्रशासन ने लगाई है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि घाटों से लेकर हाईवे तक की निगरानी के लिए तीन जोन व 32 सेक्टर मजिस्ट्रेटों, 10-10 गोताखोरों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन की ओर से हाईवे पर स्थित अस्पतालों और औराई, गोपीगंज व ऊंज थानों में बने अस्पतालों को अलर्ट किया है। हाईवे पर पांच होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जहां 400 वाहनों की पार्किंग होगी। प्रयागराज में भीड़ बढ़ने पर वाहनों को यहां रोका जाएगा।

तीन अवैध प्लॉटिंग पर चला बीडा का बुलडोजर

भदोही, (संवाददाता)। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) ने बृहस्पतिवार को तीन अवैध प्लॉटिंग ले-आउट पर बुलडोजर चलाया। पुलिस और अधिकारियों की उपस्थिति में तीन अलग-अलग अवैध प्लाटिंग ले-आउट जमींदोज किए गए। ये तीनों ले-आउट 7800 वर्ग मीटर परिक्षेत्र में विकसित किए गए थे। उप कार्यपालक अधिकारी अनीता देवी ने बताया कि बीडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र मौजा हरियांव में गाटा संख्या 62 में करीब 7800 वर्ग मीटर में देवी प्रसाद निवासी हरियांव, शालू देवी निवासी चकइनायत, कार्तिक जायसवाल निवासी चकइनायत ने अनाधिकृत रूप से भू-विन्यास (ले-आउट) विकसित किए बिना ही निर्माण करा लिया। बीडा की ओर से पहले नोटिस दी गई, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया।

कोई भी नामांकन वापस नहीं, शाखा प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित

उन्नाव, (संवाददाता)। सहकारी ग्राम विकास बैंक के पांच शाखा प्रतिनिधियों के दो दिन पूर्व हुई नामांकन प्रक्रिया में बृहस्पतिवार को एक भी पर्चा वापस नहीं हुआ। सभी जगहों पर एकल नामांकन होने से प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाणपत्र दिए गए। जिले में सहकारी ग्राम विकास बैंक की पांच शाखाए हैं। इसमें शाखा प्रतिनिधियों के लिए 20 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया हुई थी। बृहस्पतिवार को नाम वापसी होनी थी। सुबह 11 बजे से तीन बजे के बीच एक भी पर्चा वापस नहीं हुआ। इसके बाद सदर से संजीव त्रिवेदी, बीघापुर पाटन से संतोष सिंह, सफीपुर से हरिशरण गुप्ता लाला, हसनगंज से शैलेंद्र सिंह व पुरवा से ओमप्रकाश चौधरी के एकल नामांकन होने से सभी को निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी गई। सहायक निबंधक सहकारिता रवींद्र कुमार ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। किसी के भी नाम वापस न लेने पर सभी को निर्विरोध शाखा प्रतिनिधि निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र दे दिया गया।

बसंत पंचमी पर डॉ बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मंत्री ने किया हवन पूजन

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। बसंत पंचमी पर देवकाली, अयोध्या में स्थित राजकीय डॉ बृज किशोर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ विशेष पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस अवसर पर आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मंत्री दयाशंकर मिश्र ध्दयालुध् ने विधि-विधान से माँ सरस्वती का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।महाविद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। कार्यक्रम में छात्रदृछात्राओं, शिक्षकों एवं स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आशीष कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बसंत पंचमी के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस दौरान मंत्री दयाशंकर मिश्र एवं प्राचार्य डॉ. आशीष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से हवन एवं आरती की, जिससे कार्यक्रम की आध्यात्मिक गरिमा और अधिक बढ़ गई। पूजन उपरांत मंत्री दयाशंकर मिश्र ने महाविद्यालय के विभिन्न भू-भागों एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संस्थान की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। अपने संबोधन में मंत्री जी ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बढ़ते योगदान की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि महाविद्यालय के समग्र विकास हेतु हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक एवं चिकित्सीय सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ हों। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पेन का वितरण किया गया, जिससे छात्रों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि डॉ. तूलिका जैन द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन मंत्री दयाशंकर मिश्र के करकमलों द्वारा किया गया।कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय प्रशासन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समापन सरस्वती वंदना एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ।

उत्तमोत्तम प्रदेश बनाना ही उत्तर प्रदेश दिवस का लक्ष्य : प्रोफेसर रणजीत कुमार पांडेय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर गांधी स्मारक पी.जी. कॉलेज समोधपुर, जौनपुर में शनिवार को श्उत्तर प्रदेश दिवसश 2026के अवसर पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर रणजीत कुमार पांडेय द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रणजीत कुमार पांडेय ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रदेश की गौरवशाली विरासत को जानने, समझने और उसके संरक्षण हेतु सजग रहने का आह्वान किया। प्रोफेसर पांडेय ने उत्तर प्रदेश दिवस को जनोत्सव के रूप में मनाए जाने पर बल दिया।उन्होंने कहा कि गौरवशाली अतीत और सशक्त वर्तमान वाले अपने इस उत्तर प्रदेश को उत्तमोत्तम प्रदेश बनाकर विकसित देश बनाने में अपने अपने स्तर से अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते रहना है । कार्यक्रम में

उत्तर प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक योगदान पर वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त किए गए। विद्यार्थियों ने भी विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं उपलब्धियों को रेखांकित किया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह व धन्यवाद ज्ञापन डॉ विष्णु कांत त्रिपाठी ने किया । कार्यक्रम में डॉ अवधेश कुमार मिश्रा, डॉ नीलमणि सिंह, डॉ पंकज सिंह, डॉ लालमणि प्रजापति, विकास कुमार यादव, नीलम सिंह, जितेंद्र कुमार, बिंद प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह, राजेश सिंह, शिवमंगल सोनी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहीं। अंत में कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

संक्षिप्त खबरें

दो आरक्षियों पर जानलेवा हमला, बीडीसी सहित तीन गिरफ्तार

भदोही, (संवाददाता)। लखनो गांव में बुधवार की रात करीब नौ बजे एससी-एसटी और मारपीट के आरोपी को छुड़ाने की कोशिश का मामला प्रकाश में आया। आरोपी के परिजनों ने दो पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके तीन को गिरफ्तार किया है। सुरियावां थाने के आरक्षी आशीष कुमार ने तहरीर देकर बताया कि 21 जनवरी की रात नौ बजे आरक्षी शशिकांत भारती के साथ एससी-एसटी के आरोपी राजू निवासी आंबेडकर नगर को एसडीएम भदोही कार्यालय लेकर गया। वहां से रिमांड स्वीकृत होने पर जिला कारागार ले जा रहे थे। जिला कारागार में दाखिल कराने के बाद वापस सुरियावां आ रहे थे कि लखनो तिराहे के आगे पेट्रोल पंप से 100 मीटर पहले दो बाइक से छह लोग आए। तेज आवाज में गाली देकर पूछा कि मेरे लड़के को जेल में कैसे दाखिल कर दिए। मेरे साथी आरक्षी शशिकांत को जमीन पर पटककर कल्लू अनवर जान से मारने की नीयत से सिर पर ईंट से प्रहार करके घायल कर दिए। मैंने छुड़ाने की कोशिश तो मुझे भी मारने लगे। आरक्षी शशिकांत का इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने मामले में कल्लू उर्फ अनवर उर्फ शहजादे, सोनू, जुगनू, भाईजान निवासी आंबेडकर नगर, बीडीसी मनापुर प्रदीप सरोज और धीरज निवासी शिवपुर मड़ियाहू जौनपुर के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में एसपी ने बृहस्पतिवार की सुबह आरोपी भाईजान, धीरज और प्रदीप सरोज को ज्ञानपुर के विकईयाधाम से गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि तीन आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। तीन की तलाश के लिए टीम दबिश दे रही है।

जूट की कीमतों में 42 फीसदी तक का उछाल, कालीन निर्यातकों को 300 करोड़ का नुकसान

भदोही, (संवाददाता)। अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहे निर्यातकों को भारत-बांग्लादेश में उपजे तनाव के कारण नए संकट का सामना कपना पड़ रहा है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े उत्पाद भारत में सड़क मार्ग से आयात करने पर पाबंदी लगा दी है। इससे भारत में जूट यार्न की कीमतों में 42 प्रतिशत तक का उछाल आया है। जूट की बनी कालीन और अन्य उत्पादों का निर्यात सलाना लगभग 1200 करोड़ रुपये का है। जूट की कीमतों में 42 फीसदी तक उछाल आने से जूट के सामानों का उत्पादन महंगा हो गया है। पहले आर्डर बुक किए निर्यातकों के सामने पुराने दाम पर जूट के उत्पाद का निर्यात करना है। इससे निर्यातकों को 250-300 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। निर्यातकों ने बताया कि बांग्लादेश के सस्ते और सब्सिडी वाले जूट भारत में आने से भारतीय जूट उद्योग को नुकसान हो रहा था। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया (एसएएफटीए) के तहत बांग्लादेश से जूट उत्पादों के भारत में बिना ड्यूटी के आयात की छूट है। ऐसे में भारत ने सीधे-सीधे आयात प्रतिबंध न लगाकर बांग्लादेशी जूट के भारत में केवल महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही भारत प्रवेश की इजाजत दी है। भदोही के जूट कालीन निर्माताओं के अनुसार पहले मात्र 7 दिन में मनचाहे स्थान पर जूट की डिलिवरी हो जाती थी, लेकिन अब न्हावा शेवा बंदरगाह से आने में 45 दिन का समय लग रहा है।

पत्रकार के परिवार पर जानलेवा हमला, FIR के बाद भी पुलिस की सुस्ती पर उठे सवाल

देश की उपासना

मुम्बई ब्यूरो चीफ धनन्जय विश्वकर्मा। नालासोपारा (विरार): पालघर जिले के आचोले पुलिस थाना अंतर्गत श्एवरशाइन सिटीश की सवियो सोसाइटी में 15 जनवरी 2026 को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक स्थानीय पत्रकार के परिवार पर ड्रग्स के नशे में धुत हमलावरों ने न केवल जानलेवा हमला किया, बल्कि उन्हें गंभीर धमकियाँ भी दीं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज होने के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है।

घटना का विवरण प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर लगभग 12 बजे की है। पत्रकार परिवार का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता उदय विजय शेट्टी के परिवार (माँ, बहन सना और भांजी अलीशा) ने इस हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले पत्रकार के घर से सोने के जेवर और नकदी चोरी की थी। जब पीड़ित परिवार ने अपना सामान वापस माँगा, तो आरोपियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत घर में घुसकर हमला कर दिया।

हमले की भयावहता

इस हिंसक हमले में पत्रकार की पत्नी गीता जायसवाल, बेटी सविता जायसवाल सहित घर में मौजूद दो छोटे बच्चों और उनकी वृद्ध माँ को निशाना बनाया गया। आरोप है कि हमलावर ड्रग्स के नशे में थे। हमले के दौरान अपराधियों ने परिवार को जान से मारने और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने जैसी वीभत्स धमकियाँ भी दीं, जिससे पूरा परिवार और सोसाइटी के निवासी दहशत में हैं।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

आचोले पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है

धारा 79- महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना

धारा 333- घर में जबरन घुसना (House-trespass)

धारा 115(2)- स्वेच्छा से चोट पहुँचाना

धारा 352- शांति भंग करने के इरादे से अपमान

धारा 351(2)- आपराधिक धमकी

धारा 3(5)- संयुक्त देयता (Common intention)

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

इतनी गंभीर धाराएं लगने और आरोपियों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस की श्चुप्पीश चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों का दावा है कि मुख्य आरोपी के भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी उदय शेट्टी, उसके परिवार और स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी।

सोसाइटी के निवासियों की मांग है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन श्ड्रग्स पेडलर गैंगश और हमलावरों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए।

23.67 करोड़ से बनेंगे दो बाईपास, जाम से मिलेगी निजात

उन्नाव, (संवाददाता)। जिले में दो नए बाईपास के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। पहला बाईपास मौरावां और दूसरा बक्सर चंद्रिका देवी चौराहे पर बनाया जाएगा। इससे जाम की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी ने मौरावां और बक्सर में बाईपास निर्माण की कवायद शुरू की थी। पीडब्ल्यूडी अभियंताओं ने बाईपास के प्रस्तावित स्थलों का सर्वे कराया था। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब प्रदेश सरकार ने दोनों बाईपास निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसमें मौरावां बाईपास के लिए 20.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ पहली किस्त के रूप में 10.33 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। बक्सर में मां चंद्रिका देवी मंदिर के पास चौराहे पर बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए करीब तीन करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। बाईपास निर्माण से लखनऊ, रायबरेली व फतेहपुर जनपद तक आवागमन आसान होगा। वाहन शहर में आए और जाम में फंसे बिना सीधे निकल सकेंगे। निर्माण पूरा करने के लिए 12 माह का समय तय किया गया है। मौरावां। बाईपास का निर्माण मौरावां कस्बे के आबादी भाग से शुरू कराया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 2.8 किलोमीटर होगी। इस बाईपास का उद्देश्य आबादी भाग के अंदर आने वाले वाहनों को बाहर से ही निकालकर हाईवे से मिलाना है। इससे बिहार कस्बे व दही चौकी मोड़ की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को कस्बे के बाहर से बाईपास के जरिए निकाला जाएगा। वाहन चालक मोहनलालगंज, लखनऊ, बाराबंकी व रायबरेली के लिए बाईपास से ही निकल जाएंगे। इससे कस्बे में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। बक्सर में करीब 900 मीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा। बक्सर में ही प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी का मंदिर है। यहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में दूसरे जनपदों से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मार्ग फतेहपुर को भी प्रमुखता से जोड़ता है। बाईपास निर्माण से मार्ग का चौड़ीकरण भी होगा। इसके बन जाने से एक तरफ क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। वहीं बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को भी जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। वाहन सवार भी एक तरफ फतेहपुर तो दूसरी ओर वाया बिहार होते हुए लखनऊ, बाराबंकी व रायबरेली का आवागमन कर सकेंगे। दो बाईपास निर्माण के लिए बजट जारी हो गया है। विभागीय स्तर पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 दिन में इसे पूरा करा लिया जाएगा। इसके बाद अनुबंध पत्र गठन सहित अन्य विभागीय कार्रवाई पूरी कराकर काम शुरू कराया जाएगा। एक साल में दोनों का निर्माण पूर्ण कराना है।-हरदयाल अहिरवार, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।